समेत, सहमत वित्तीय एवं वाणिज्यिक शर्तों का अनुपालन न किए जाने के मामले में, जहां कहीं भौतिक और तकनीकी रूप से व्यावहारिक हो, एन टी पी सी को यह अनुमति दी गयी है कि ऐसे मामलों में वे अपने संबंधित विद्युत केन्द्रों से विद्युत सप्लाई बन्द कर दें अथवा प्रतिबंधित कर दें।

(2) राज्य बिजली बोर्डों से, एक्सी कवरेज से अधिक विद्युत आहरण के लिए पैनल दरें प्रभारित की जाएंगी।

(3) 31 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार संचयित बकाया राशियों की वसूली, चार वार्षिक किश्तों में 1020.50 रु० की राशि संबंधित राज्यों की केन्द्रीय आयोजना सहायता से एन टी पी सी को देय वसूलियों को वसूल करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से, 31 मई, 1992 की स्थिति के अनुसार चार वार्षिक किश्तों में 745.31 करोड़ रुपये देय की वसूलियों से भी की जा रही हैं।

(4) चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ओर बकाया राशियों को शीघ्र भुगतान और चालू बिलों के नियमित भुगतान हेतु जोर दिया जा रहा है।

Supply of Coal to new Thermal Power Stations in Madhya Pradesh

950. SHRI AJIT P.K. JOGI:
CHOWDHRY HARI SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have given its accord to make the coal available to certain newly proposed Thermal Power Stations in Madhya Pradesh;

(b) it so, what is the requirement of coal for the said projects and what quantum of coal has been allocated to them;

(c) whether State Government have also requested to increase the supply of coal for their other power projects; and

(d) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Yes, Sir. The Standing Linkage Committee (Long-Term) of the Ministry of Coal on Thermal Power Stations in its meeting held on 27.1.1994 have agreed to coal linkage for Korba (West) Thermal Power Station Units 5 & 6 (2×210MW) in Madhya Pradesh under private sector. The ultimate coal requirement is indicated as 2.35 million tons per annum from August, 1998 onwards. The requirement of coal is of the order of 2.30 million tons per annum at 80% plant load factor.

(c) and (d) Coal supplies to thermal power stations are arranged on quarterl basis as per the linkages provided by the Standing Linkage Committee (Short-term) of the Ministry of Coal. Supply of coal to power houses is given highest priority. Supplies of coal to power stations in Madhya Pradesh is closely monitored and corrective action taken whenever necessary to sustain power generation.

पम्प सेटों में सुधार करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव

951. **श्री अजीत जोगी:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पम्प सेटों में सुधार करने के लिए और उन्हें बिजली के कनेक्शन देने के लिए 1993-94 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से इन पम्पों में सुधार किया गया है; और

(ग) इस कार्य पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों से पंपसेटों में सुधार लाने हेतु, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए गए हैं राज्य बिजली